



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 28, 2015/ज्येष्ठ 7, 1937

No. 196]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 28, 2015/JYAISTHA 7, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 25 मई, 2015

सं. टीएमपी/21/2015—वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम (1963 का 38) की धारा 48 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) से प्राप्त वीपीटी के पूर्वी घाट और पश्चिम घाट की बर्थों पर स्थापित होने वाली 100 टन हार्वर मोबाइल क्रेन के प्रयोग की प्रशुल्क दरों के निर्धारण प्रस्ताव को निम्नलिखित आदेश द्वारा निपटाता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

केस संख्या टीएमपी/21/2015—वीपीटी

विशाखापट्टनम पत्तन न्यास

---

आवेदक

कोरम

- (i) श्री टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन—सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री सी. वी. सिंह —सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(मई 2015 के 15वें दिन पारित)

यह केस, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) से प्राप्त, वीपीटी के पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट की बर्थों पर स्थापित होने वाली, 100 टन हार्वर मोबाइल क्रेन के प्रयोग की प्रशुल्क दरों को निर्धारित करने के प्रस्ताव से सम्बंधित है।

2.1. वीपीटी द्वारा अपने दिनांक 24 मार्च, 2015 के प्रस्ताव में बनाये गये मुख्य बिंदुओं को सारांश में नीचे दिया गया है।

- (i) पोर्ट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की बर्थों पर, लाइसेंस के आधार पर, कार्यों प्रहस्तन के संचालन हेतु, दो हार्वर मोबाइल क्रेन जिनमें प्रत्येक की क्षमता 100 टन को स्थापित करने का प्रस्ताव करता है।
- (ii) टीएमपी ने अपनी अधिसूचना जी नं. 7 दिनांक 5 जनवरी, 2015 में, प्राइवेट संचालकों द्वारा पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट (पीपीटी) पर स्थापित, 100 टन हार्वर क्रेन के प्रयोग की दरों को अधिसूचित किया है। पीपीटी के केस, में अधिसूचित दरों को संदर्भ प्रशुल्क माना जा सकता है तथा अधिसूचित जाये।

- (iii) यद्यपि, 100 टन (एचएमसी) के लिए कीमत संगणना की गयी है, जिसको ड्राफ्ट दरों के स्केल के साथ दिया गया है।

2.2. 100 टन हार्वर मोबाइल क्रेन के प्रतिटन प्रहस्तन दर पर पहुंचने के लिए, वीपीटी द्वारा की गयी संगणना निम्न प्रकार है :

क्र.स.	विवरण	लाख में		
		ड्राई बलक	ब्रेक बलक	अन्य
I	<b>अधिकतम क्षमता</b>			
(i)	कार्गो भाग	100%	100%	100%
(ii)	कार्गो प्रहस्तन दर टन में प्रति दिन	12500	6000	3750
(iii)	कार्गो प्रहस्तन दर टन में प्रति घंटा	744	357	223
(iv)	एक वर्ष में कुल कार्य दिवस	4000	4000	4000
(v)	विचारार्थ एच एम सी की संख्या	2	2	2
(vi)	व्यक्तिगत कार्गो क्षमता (i*iii*iv*v)	5,952,381	2,857,143	1,785,714
(vii)	वार्षिक प्रहस्तन क्षमता (लाख टन में)	59.52	28.57	17.86
(viii)	वार्षिक प्रहस्तन क्षमता (मिलियन टन में)	5.95	2.86	1.79
II	<b>पूँजी लागत</b>			
(i)	100 टन मोबाइल हार्वर क्रेन की कीमत (€ 2,890,000*68.74)		1986.59	
(ii)	2 ग्रेव की कीमत (€ 320,000 * रु 68.74)		219.97	
(iii)	अतिरिक्त 2 ग्रेव की कीमत (€ 320,000 * रु 68.74)		219.97	
(iv)	सागर माल ढुलाई लागत (€ 330,000 * रु 68.74)		226.84	
(v)	एक क्रेन की कीमत		2653.36	
(vi)	कुल 2 क्रेन की कीमत		5306.73	
(vii)	सीमा प्रशुल्क एच एम सी की कीमत के 25 % की दर से		1326.68	
(viii)	अन्य पूँजी कीमतें - पूँजी कीमत का 5% की दर से		265.34	
(ix)	<b>कुल पूँजी कीमत (vi to viii)</b>		<b>6898.75</b>	
III	<b>प्रचालन लागत प्रति वर्ष</b>			
(i)	ईंधन लागत (डीजल - 4000 घंटे. 70 लीटर प्रति घंटा की दर से, रु 55.95 प्रति लीटर *2)		313.32	
(ii)	रख रखाव और मरम्मत उपकरण की कीमत के 5% की दर से		344.94	
(iii)	बीमा (पूँजी कीमत के 1% की दर से)		68.99	
(iv)	अवमूल्यन पूँजी कीमत का 10 %		689.87	
(v)	लाइसेंस प्रशुल्क (रु 249.37 प्रति वर्ग मीटर. 500 वर्ग मीटर के लिए प्रति वार्षिक ई क्यू पर)		1.25	
(vi)	लाइसेंस प्रशुल्क (रु 213.74 प्रति वर्ग मीटर. 500 वर्ग मीटर के लिए प्रति वार्षिक ई क्यू पर)		1.07	
(vii)	अन्य खर्चे पूँजी कीमत का 5 %		344.94	
	<b>कुल प्रचालन कीमत (i से vi)</b>		<b>1764.37</b>	

IV	निवेशित पूँजी पर आय 16 % की दर से	1103.80		
V	अनुमानित वार्षिक राजस्व की आवश्यकता:			
(i)	कुल प्रचालन कीमत	1764.37		
(ii)	निवेशित पूँजी पर आय	1103.80		
(iii)	कुल राजस्व की आवश्यकता	2868.17		
VI	कीमत प्रति टन	ड्राई बल्क	व्रेक बल्क	अन्य
(i)	कुल वार्षिक राजस्व की आवश्यकता (रु लाख में)	2868.17	2868.17	2868.17
(ii)	क्षमता (लाख टन)	59.52	28.57	17.86
(iii)	विदेशी मालवाहक तटवर्ती कार्गो के लिए - पिछले 5 साल का अनुपात			
	विदेशी	68.35%	95.65%	--
	तटवर्ती	31.65%	4.55%	--
(iv)	कीमत प्रति टन रुपए में			
	(अ). विदेशी	55.17	102.04	160.62
	(ब). तटवर्ती	33.10	61.22	96.37

3. लाइसेंस के आधार पर स्थापित होने वाली 100 टन एचएमसी के किराये की दरों वाले वीपीटी के प्रस्ताव को स्वीकृति की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, मुख्य पत्तन न्यास की प्रशुल्क नीति 2015 की धारा 9.1 और 9.2 का संदर्भ देना प्रासंगिक है, जो अधिकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा लगाई गयी दरों का नियमन करता है। खण्ड 9.1 यह निर्धारण करता है कि जहां प्राधिकार व्यवस्था सेक्शन 42(3) के अंतर्गत, वीओटी रियायत समझौते के अलावा, ऐसी सेवाओं के लिए अधिकतम दर, सम्बंधित मुख्य पत्तन न्यास द्वारा फाइल प्रस्ताव पर आधारित होगी। वर्णित किये गये मार्गदर्शों का खण्ड 9.2 निर्धारण करता है कि यदि सम्बंधित मुख्य पत्तन न्यास पर किसी विशेष सेवा सुविधा के लिए अधिकतम दर निर्धारित नहीं है इस स्थिति में न्यास, अन्य किसी मुख्य पत्तन न्यास पर उस जैसी सेवा, सुविधा के निर्धारित प्रशुल्क को अपना सकता है। यदि, किसी भी मुख्य पत्तन न्यास पर प्रशुल्क निर्धारित नहीं है या निर्धारित दर कार्गो सेवा/सुविधा का प्रतिनिधित्व नहीं करती तब वह पत्तन न्यास, 2008 के दिशा-निर्देशों के सिद्धांतों के पालन, इष्टतम क्षमता के संदर्भ के साथ या निर्धारण क्षमता के आधार पर प्रस्ताव फाइल कर सकता है। (सेवा/सुविधा/उपकरण की तकनीकी विनिर्देशन संदर्भ के साथ) पत्तन न्यास का प्रस्ताव सेवा प्रदाताओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रदर्शन मानकों को शामिल करते हुए प्रशुल्क को प्रदर्शन मानकों से जोड़ कर प्रस्तावित करना चाहिए।

4.1. वीपीटी द्वारा 24 मार्च, 2015 को जमा किए गए प्रस्ताव का अध्ययन करने एवं प्रशुल्क नीति 2015 की शर्तों के प्रकाश में सूचना की कमी के बारे में वीपीटी को हमारे दिनांक 07 अप्रैल 2015 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था। वीपीटी ने अपने 16 अप्रैल, 2015 के पत्र के माध्यम से हमारे द्वारा इंगित सूचना की कमी की अनुपलब्धता के विषय में अपना जवाब प्रस्तुत किया है। हमारे द्वारा इंगित सूचना की कमी एवं उनके संदर्भ में वीपीटी द्वारा जानकारी नीचे सारणीबद्ध है :

क्र.सं.	हमारे द्वारा अनुभव की गयी कमी	वीपीटी द्वारा दिया गया जवाब
(i)	वीपीटी ने जहां एक तरफ पारादीप पत्तन न्यास के लिए, प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत 100 टन एचएमसी का प्रशुल्क (प्रशुल्क आदेश सं. टीएमपी/30/2014/पीपीटी दिनांक 28 नवंबर, 2014 जी. न. 7 दिनांक 5 जनवरी, 2015 द्वारा अधिसूचित) अधिसूचित करने का आग्रह किया है। वहीं दूसरी तरफ वीपीटी ने 100 टन एचएमसी के लिए अन्य माल वाहक समूह के लिए अपनी गणना प्रस्तुत की है एवं एसओआर में दरों का प्रस्ताव पत्तन द्वारा की गई गणना के आधार पर किया है। यह देखा गया है कि पत्तन द्वारा अपनी गणनाओं के आधार पर की गई दरों की संस्तुति, प्राधिकरण द्वारा पीपीटी के लिए अधिसूचित दरों से भिन्न है, जिसे पत्तन ने अधिसूचित करने का आग्रह किया है। उदाहरण के तौर पर 100 टन एचएमसी के लिए वीपीटी द्वारा, ब्रेक बल्क एवं अन्य माल के लिए प्रस्तावित दर 102.04 प्रतिटन एवं 160.62 प्रतिटन क्रमशः प्रस्तावित है। जबकि 100 टन	वीपीटी ने पारादीप पत्तन पर प्राधिकरण द्वारा 100 टन मोबाइल क्रेन के प्रयोग के लिए, स्वीकृत शुल्क की दर (प्रशुल्क आदेश संख्या टीएमपी/30/2014-पीपीटी दिनांक 28 नवंबर, 2014 एवं जी. न. 7 द्वारा दिनांक 5 जनवरी 2015 को अधिसूचित) को अधिसूचित करने का आग्रह किया है, क्योंकि तैनाती का प्रारूप एक समान है। वीपीटी द्वारा उसके दिनांक 24 मार्च, 2015 के पत्र द्वारा उसकी गणना के आधार पर प्रस्तावित दरों को वापिस ले लिया गया है। तदनुसार वीपीटी, प्रशुल्क नीति 2015 के प्रासंगिक अधिनियमों के आधार पर एक स्पष्ट प्रस्ताव फाइल कर रही है। वीपीटी में 100 टन एचएमसी की

	<p>एचएमसी किराये की दर, पीपीटी पर दिनांक 28 नवंबर, 2014 के आदेश में 114.97 प्रतिटन एवं 183.95 प्रतिटन क्रमशः है।</p> <p>यदि वीपीटी, पीपीटी पर 100 टन एचएमसी जैसी दर को अधिसूचित करने का प्रस्ताव देता है, तब भी 100 टन एचएमसी के किराये की दर की गणना एवं एसओआर में उसी दर को प्रस्तावित करना, उसके इस प्राधिकरण को, पीपीटी के संदर्भ में दरों को अधिसूचित करने के लिए किए गये अनुरोध के अनुरूप नहीं है। अतः पीपीटी प्रशुल्क नीति 2015 के संदर्भित अधिनियमों के तहत एक अलग प्रस्ताव प्रस्तुत करें।</p>	<p>स्थापना में लाइसेंस के आधार पर कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है। अतः वीपीटी यह प्रस्ताव करता है कि पीपीटी के समरूप सुविधाओं की उन्हीं उच्चतम सीमाओं का प्रयोग प्रशुल्क नीति 2015 के अनुच्छेद 9.2 का पालन करते हुए हो।</p>															
(ii)	<p>प्राधिकरण ने पूर्व में अपने आदेश संख्या टीएमपी/16/2012-वीपीटी दिनांक 16 जून, 2010 के माध्यम से, वीपीटी पर 100 टन एचएमसी के किराये की राशि को स्वीकृत सेवा प्रदाताओं के लिए अनुमोदित किया था। बाद में, अपने दिनांक 28 सितंबर 2012 के आदेश में वीपीटी के अनुरोध पर जून 2010 में, तय शुल्क दरों में संशोधन किया गया था, चूंकि 100 टन एचएमसी के किराए की दर इसके खुद के पत्तन के लिए पहले से ही स्वीकृत है, वीपीटी यह स्पष्टीकरण दे कि उसके वर्तमान प्रस्ताव में पीपीटी पर 100 टन एचएमसी किराए की दर का अनुमोदन किस प्रकार प्रशुल्क नीति 2015 के परिच्छेद 9.2 के अनुरूप है।</p>	<p>24 मार्च, 2015 का वर्तमान प्रस्ताव एवं टीएमपी आदेश सं. टीएमपी/16/2012- वीपीटी दिनांक 16 जून, 2010 निम्न प्रकार भिन्न है:</p> <table border="1"> <tr> <th>क्र. सं.</th><th>टीएमपी आदेश दिनांक</th><th>प्रस्ताव दिनांक</th></tr> <tr> <td></td><td>16.6.2010</td><td>24.3.2015</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>किराये के आधार पर</td><td>राजस्व का बटवारा</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>एमजीटी का एक एमएमटी</td><td>कोई एमजीटी नहीं</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>उपलब्धियों का कोई स्तर नहीं</td><td>पीपीटी के अनुसार उपलब्धियों का स्तर समाहित</td></tr> </table>	क्र. सं.	टीएमपी आदेश दिनांक	प्रस्ताव दिनांक		16.6.2010	24.3.2015	1.	किराये के आधार पर	राजस्व का बटवारा	2.	एमजीटी का एक एमएमटी	कोई एमजीटी नहीं	3.	उपलब्धियों का कोई स्तर नहीं	पीपीटी के अनुसार उपलब्धियों का स्तर समाहित
क्र. सं.	टीएमपी आदेश दिनांक	प्रस्ताव दिनांक															
	16.6.2010	24.3.2015															
1.	किराये के आधार पर	राजस्व का बटवारा															
2.	एमजीटी का एक एमएमटी	कोई एमजीटी नहीं															
3.	उपलब्धियों का कोई स्तर नहीं	पीपीटी के अनुसार उपलब्धियों का स्तर समाहित															
(iii)	<p>वीपीटी का प्रस्ताव, प्रशुल्क नीति 2015 के परिच्छेद 9.3 के अनुसार, सेवा प्रदाताओं के शुल्क क्रमबद्ध करने के लिए, इनके उपलब्धियों के स्तर की प्राप्ति के बारे में नहीं बताता</p>	<p>वीपीटी यह प्रस्तावित करता है कि प्रशुल्क आदेश टीएमपी/30/2014-वीपीटी दिनांक 28 नवंबर 2014 जी सं. 7 दिनांक 5 जनवरी, 2015 द्वारा अधिसूचित दर को पीपीटी पर 100 टन मोबाइल हार्वर क्रेन के लिए पूर्ण रूप से, उपलब्धियों के स्तर सहित अनुसरण करेगा।</p>															
(iv)	<p>प्रस्ताव में प्रत्याषित अनुज्ञापति/संभावित प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं के नाम उनके संपर्क जानकारी जैसे डाक पता, संपर्क अधिकारी, दूरभाष एवं फ़ैक्स संख्या, ई-मेल इत्यादि संदर्भित विषय पर विचार विमर्श के लिए नहीं किया गया है।</p>	<p>प्रत्याषित अनुज्ञापति/संभावित प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं की सूची उपलब्ध करायी गयी है।</p>															

#### 4.2. इसके अतिरिक्त वीपीटी ने अधोलिखित प्रस्तुत किया है :

- वीपीटी ने राजस्व बटवारे माडल के आधार पर कार्गो प्रहस्तन संचालन के लिए 100 टन क्षमता की 2 एचएमसी लाइसेंस के आधार पर स्थापित करने का प्रस्ताव करता है।
- क्योंकि वीपीटी पर इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए शुल्क की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यह प्रस्ताव किया जाता है जैसे "मुख्य पत्तनों के शुल्क निर्धारण की नीति 2015 के अनुच्छेद 9.2 में है, उसके अनुसार ही, पीपीटी के समरूप सुविधाओं के शुल्क को, टीएमपी द्वारा अधिसूचित किया जाय।

- (iii) अतः वीपीटी का यह प्रस्ताव है कि जैसे वीपीटी पर 100 टन एचएमसी के लिए टीएएमपी जी नं. 7 दिनांक 5 जनवरी, 2015 की अधिसूचित दरों का प्रयोग निजी चालकों द्वारा स्थापित 100 टन एचएमसी के शुल्क के लिए भी किया जाए।
- (iv) शुल्क की दर का आधार (एसओआर) प्रदर्शन स्तर का आधार एवं प्रदर्शन स्तर आधारित शुल्क का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है।
- (v) वीपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव में प्रस्तावित आधारभूत दर इस प्रकार है :

कार्गो प्रकार	औसत टन भार	दर प्रति टन रुपए में (विदेशी)
ड्राई बल्क	12500	55.18
ब्रेक बल्क	6000	114.97
अन्य	3750	183.95

4.3. उपरोक्त के प्रकाश में वीपीटी ने अपने जवाब पर विचार करने का अनुरोध किया है तथा प्रशुल्क आदेश सं. टीएएमपी/30/2014-वीपीटी दिनांक 28 नवंबर, 2014 जी नं. 7 दिनांक 5 जनवरी, 2015 द्वारा अधिसूचित के आधार पर 100 टन एचएमसी के वीपीटी पर प्रयोग दर को ही अधिसूचित करने का आग्रह किया है।

5. निर्धारित विचार विमर्ष के तरीके के अनुसार वीपीटी के दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के प्रस्ताव को, सम्बद्ध प्रयोगकर्ता/प्रयोगकर्ता संस्थाओं/सेवा प्रदाताओं (वीपीटी की सलाह पर) को, टिप्पणियों जिसकी अंतिम दिनांक 28 अप्रैल, 2015 थी, के लिए भेजा गया। इसे साथ में वीपीटी एवं प्राधिकरण को भी संदर्भित किया गया था। प्रयोगकर्ता/प्रयोगकर्ता संस्थाओं/सेवा प्रदाताओं आदि से प्राप्त टिप्पणियों को फीडबैक जानकारी के रूप में भेज दिया गया। वीपीटी ने दिनांक 5 मई, 2015 को अपने पत्र में प्रयोगकर्ता/प्रयोगकर्ता संस्थाओं एवं सेवा उपलब्धकर्ताओं की टिप्पणियों पर अपने मत प्रकट किए हैं।

6. इस संबंध में विचार विमर्ष की कार्यवाही के अभिलेख इस प्राधिकरण के कार्यालय में उपलब्ध हैं। सम्बंधित समूह से प्राप्त की गई विषेज्ञ टिप्पणियों को प्रासंगिक समूहों को अलग से भेजा जाएगा तथा इन ब्यौरों को हमारी वेब साइट <http://tariffauthority.gov.in> पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

7. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गयी सूचनाओं के संदर्भ की संपूर्णता में निम्नलिखित स्थिति उभरती है :

- (i) विशाखापट्टनम पत्तन न्यास (वीपीटी) द्वारा, दो 100 टन मोबाइल हार्वर क्रेन का, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर कार्गो प्रहस्तन संचालन हेतु, लाइसेंस के आधार पर करने के लिए शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव है। वीपीटी ने, प्रस्तावित किया है कि इस प्राधिकरण ने अपने 5 जनवरी, 2015 के आदेश द्वारा, पैरादीप पोर्ट ट्रस्ट (वीपीटी) के मामले में जो शुल्क अधिसूचित किया था उसको 'संदर्भ प्रशुल्क' मानकर अपनाया जाए।

इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं. टीएएमपी/30/2014-वीपीटी दिनांक 28 नवंबर, 2014 के द्वारा, हार्वर मोबाइल क्रेन (एचएमसी) की उच्च प्रशुल्क सीमा के आदेश को पारित किया था, जिसको वीपीटी ने बिना किसी सुधार के अपनाने का प्रस्ताव दिया है।

- (ii) जहाज एवं नौ परिवहन मंत्रालय ने मुख्य पत्तन न्यासों के शुल्क निर्धारण 2015 के लिए नीति जारी की है, जिसे इस प्राधिकरण ने भारत के गजट में 27 जनवरी, 2015 को जी नं. 30 के माध्यम से अधिसूचित किया है तथा उपर्युक्त प्रशुल्क नीति 13 जनवरी, 2015 से लागू हो गयी है। प्रशुल्क नीति 2015 के अनुच्छेद 9.1 के अनुसार —“जहां भी अगर अधिकार पत्र की व्यवस्था सेक्शन 42 (3) के अधीन, वीओटी रियायत व्यवस्था के अलावा है, ऐसी सेवा के लिए उच्चतम शुल्क दर निर्धारित की जाएगी। इस उद्देश्य से इन शुल्कों के लिए प्रस्ताव की पुरुआत सम्बद्ध मुख्य पत्तन न्यास द्वारा, यह निर्धारण के बाद कि यह प्राधिकृत सेवा, प्रशुल्क नियंत्रण के क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा तब इस प्राधिकरण को भेजा जाए।” प्रस्ताव सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रदर्शन मापदंड को शामिल करेगा व प्रदर्शन मापदंड से सम्बंधित प्रशुल्क प्रस्तावित किया जाना चाहिए व उक्त नीति का अनुच्छेद 9.2 बताता है कि “अगर इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत तत्सम्बंधित प्रमुख पत्तन न्यास पर किसी सेवा सुविधा के लिए प्रशुल्क की उपरी सीमा न निर्धारित करने की दशा में, पत्तन किसी भी अन्य प्रमुख पत्तन न्यास पर इस प्रकार की सेवा/सुविधा के लिए निर्धारित प्रशुल्क को अंगीकार करेगा।” किसी भी प्रमुख पत्तन न्यास में प्रशुल्क न निर्धारित करने या निर्धारित दर विचारित कार्गो/सेवा/सुविधा को उचित दशा में न दर्शाने की दशा में, पत्तन न्यास 2008 के दिशा निर्देशनों का

अनुसरण करते हुए अधिकतम क्षमता के संदर्भ में प्रस्ताव दायर कर सकता है या दरित क्षमता पर आधारित [सेवा/सुविधा/उपकरण के तकनीकी विषिष्टता के संदर्भ में] पतन न्यास का प्रस्ताव सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्रदर्शन मापदंड को शामिल करेगा व प्रदर्शन मापदंड से संबंधित प्रभुत्व प्रस्तावित किया जाना चाहिए।" उक्त प्रभुत्व नीति 2015 के अनुच्छेद 9.1, 9.2 व 9.3 में निर्धारित प्रावधानों का पालन करते हुए मामला विस्लेषित किया जाता है व वर्तमान प्रस्ताव को 2015 के दिशा निर्देशनों के अनुच्छेद 9.1 व 9.3 द्वारा शासित करने की जरूरत है। आगे वीपीटी ने भी यह कहा है कि जैसा कि इस प्रकार की व्यवस्था के लिए वीपीटी पर कोई उपरी प्रभुत्व दर निर्धारित नहीं की गई है, प्रमुख पत्तन न्यासों के लिए 2015 की प्रभुत्व निर्धारण नीति के अनुच्छेद 9.2 के द्वारा यह प्रस्तावित किया जाता है कि वीपीटी पर इस प्राधिकरण द्वारा समान सुविधा के लिए अधिसूचित प्रभुत्व की उपरी सीमा को अंगीकार किया जाए।

- (iii) यहां यह बताना उचित होगा कि इस प्राधिकरण ने पहले आदेश सं. टीएएमपी/16/2012-वीपीटी दिनांक 16 जून 2010 द्वारा अधिकृत सेवा प्रदाता को पत्तन द्वारा वीपीटी पर 100 टन एचएमसी के लिए किराया भाड़ा अनुमोदित किया है। तत्पश्चात् 28 सितंबर, 2012 के आदेश द्वारा, वीपीटी के अनुरोध पर जून 2010 के आदेश में अनुमोदित प्रभुत्व में बदलाव किया गया था। चूंकि अपने पत्तन के लिए 100 टन एचएमसी के लिए किराया भाड़ा पूर्वतः अनुमोदित है, वीपीटी को पूछा गया कि 2015 के प्रभुत्व नीति के अनुच्छेद 9.5 में वीपीटी पर 100 टी एचएमसी के लिए अंगीकार करने के वर्तमान प्रस्ताव को अधिसूचित करने को न्यायसंगत ठहराये। जवाब में, वीपीटी ने दिनांक 24 मार्च, 2015 के प्रस्ताव को जो राजस्व आधारित पर हैं, दिनांक 16 जून 2010 के आदेश की तुलना में, जो कि उच्च किराए के आधार पर आधारित है को भागीदारी के आधार पर न्यायसंगत ठहराने की कोषिष की। दिनांक 16 जून, 2010 के आदेश में बिना प्रदर्शन मानदंड के 1 एमएमटी का एमजीटी है, जबकि वर्तमान प्रस्ताव बिना एमजीटी जरूरत के है, लेकिन यह प्रदर्शन मानदंड शामिल करता है। वीपीटी द्वारा अपने स्वयं के दर अंगीकार करने के बजाए वीपीटी द्वारा दिए गए दरों के पालने करने हेतु दिए गए तर्क संतुष्टि पूर्ण पाये जाते हैं।
- (iv) जैसा कि टीएएनजीईडीसीओ ने ठीक ही बताया, वीपीटी के प्रस्ताव पर आधारित वर्ष 2010 में प्रारंभिक अनुमोदित खंड क्रम दरें बदली गईं व अक्टूबर, 2012 में वीपीटी के अनुमति के आधार पर फिर समान दर निर्धारित की गई, अब वीपीटी ने वीपीटी पर एचएमसी के लिए निर्धारित खंडक्रम दरों को अंगीकार करने का प्रस्ताव किया है। यद्यपि इस संबंध में टीएएनजीईडीसीओ टिप्पणियों की एक प्रति भेजकर वीपीटी की टिप्पणियां मांगी गईं। खंड क्रम दरों को वापिस लाने के कारण अव्याख्यत है। चूंकि वीपीटी के लिए अनुमोदित दरों को अंगीकार करने का वीपीटी का प्रस्ताव जो कि खंडक्रम है 2015 के प्रभुत्व नीति के अनुसार है, प्रस्ताव विचार के लिए लिया जाता है।
- (v) टीएएनजीईडीसीओ द्वारा बताए गए अतिरिक्त ड्राईबल्क कार्गो के प्रति मी. टन प्रहस्तन भार के संबंध में, वीपीटी का दो एचएमसी को लगाने का प्रस्ताव पत्तनों के उत्तम प्रदर्शन मापदंड एवं कार्यवृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से है। वीपीटी यह आशा करती है कि इसमें टीएएनजीईडीसीओ जैसी उपयोगकर्ता के लिए पत्तन संबंधी भाड़े के बचत के रूप में परिलक्षित होगी।
- (vi) जैसा कि पहले बताया गया है, वीपीटी ने दिनांक 28 नवंबर, 2014 के आदेश द्वारा वीपीटी पर एचएमसी के लिए तय की गई प्रभुत्व दर को अंगीकार करने का प्रस्ताव किया है, जो कि 5 जनवरी, 2015 के भारत सरकार के गजट में अधिसूचित किया गया था। 2015 की प्रभुत्व नीति जो भारत सरकार द्वारा तत्पश्चात् घोषित की गई, जो 13 जनवरी, 2015 से प्रभाव में आयी, धारा 3.2 के अनुसार प्रभुत्व मुद्रास्फीति से स्वचालित तौर पर सूचिबद्ध होगी बशर्ते कि द्वितीय वर्ष से आगे प्रदर्शन मानदंड प्राप्त हो। यद्यपि वीपीटी मार्च, 2015 में प्रस्ताव दायर कर चुकी है। प्रभुत्व नीति 2015 के 13 जनवरी, 2015 से प्रभावी होने के पश्चात्, वीपीटी ने मुद्रास्फीति से प्रभुत्व के स्वचालित सूचिबद्ध प्रस्ताव को प्रदर्शन मापदंड प्राप्त होने की दशा में नहीं रखा है। यहां यह बताना तर्कसंगत है कि दिनांक 13 फरवरी, 2015 को इस प्राधिकरण द्वारा नवीन मंगलौर पत्तन न्यास पर सेवा प्रदाताओं द्वारा दी गई एचएमसी के लिए प्रभुत्व तय करने के लिए पारित आदेश का पैरा 10 (xviii) बताता है कि :

*"उक्त प्रभुत्व नीति की धारा 9.3 के अनुसार जहां भी भाग 42(3) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यवस्थाएं बीओटी रियायत समझौते से अलग हैं, वहां प्राधिकरण द्वारा उन सेवाओं के लिए स्वीकृत प्रभुत्व इन दिशा निर्देशनों की धारा 2.8 में निर्धारित स्वचालित सूचिबद्ध होने की दशा में धारा 3.2 के अनुसार प्रमुख पत्तन न्यास द्वारा प्रदर्शन मापदंड पूरा होने की दशा में द्वितीय वर्ष से आगे लागू होगा। अगर प्रदर्शन मापदंड नहीं पूरा किया जाता है तो अगले वर्ष कोई भी सूचीकरण नहीं दिया जाएगा।"*

*एनएमपीटी ने इसके द्वारा प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं के द्वारा तैनात एमएचसी के लिए प्रभुत्व के निर्धारण के लिए प्रस्ताव दायर किया है। आगे, एनएमपीटी ने प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा तैनात एमएचसी के लिए प्रस्तावित प्रभुत्व के लिए 2008 के दिशा निर्देशनों में निर्धारित मानकों को अंगीकार किया है। जैसा कि आदेश के प्रथम भाग में कहा गया है, एनएमपीटी ने अपने इस प्रस्ताव में संदर्भ मानक स्तर से 1000 टन अधिक कार्य निष्पादन प्राप्त करने की दशा में आधार किराये में 5 प्रतिषत*

की वृद्धि को इनाम के तौर पर कार्य निष्पादन संबंधित प्रशुल्क व कार्य निष्पादन के संदर्भ मानक स्तर के लिए प्रस्ताव किया है। तदनुसार, एनएमपीटी द्वारा प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा तैनात 100 टन एमएचसी के लिए उचित टिप्पणी द्वितीय वर्ष के शुरुवात होने के प्रभावी तारीख से स्वीकृत प्रशुल्क पर पत्तन को सूचीकरण लायक बनाने के लिए एनएमपीटी के दरों के पैमाने में निर्धारित किया गया है।”

दिनांक 21 मार्च, 2015 के आदेश में एनएमपीटी पर पत्तन के 63 टन क्षमता एचएमसी के लिए प्रशुल्क के निर्धारण के लिए पारित आधार कार्य निष्पादन मानक स्तर के प्राप्त होने की दशा में, द्वितीय वर्ष के शुरुवात के प्रभावी दिनांक से स्वीकृत प्रशुल्क पर पत्तन को सूचीकरण लागू करने योग्य बनाने के लिए एनएमपीटी के एसओआर में एक उचित टिप्पणी निर्धारित की जाती है। प्रशुल्क नीति 2015 के उचित धाराओं के अनुसार एनएमपीटी के समान मामलों में अंगीकार किए गए पद्धति का अनुसरण करते हुए, वीपीटी के एसओआर में जैसा कि नीचे दिया गया है, एक उचित टिप्पणी दी जाती है:

“इस आदेश के कार्यान्वयन के लागू होने के एक वर्ष पूरा होने से, 12500 मी. टन ड्राई बल्क कार्गो के लिए 6000 मी.टन ब्रेक बल्क कार्गो के लिए व 3750 टन अन्य कार्गो के लिए औसत प्रतिदिन क्रेन कार्य निष्पादन के संदर्भ मानक स्तर के लिए दर औसत के प्रतिदिन क्रेन कार्य निष्पादन के संदर्भ स्तर को प्राप्त होने की दशा में वर्ष 2015 के प्रशुल्क नीति की धारा 2.8 के अनुसार 01 जनवरी, 2015 व उचित वर्ष के 01 जनवरी, के बीच होने वाले भारत सरकार द्वारा घोषित थोक मूल्य सूचकांक में बदलाव के 100 प्रतिशत की सीमा तक मुद्रास्फीति की दर को प्राप्त करने के लिए वार्षिक तौर पर सूचीकरण किया जाएगा। क्रेन के औसत कार्य निष्पादन के संदर्भ मानक स्तर की गणना एक वर्ष में प्रहस्तनित किए गए कुल टन भार (कार्गो) को तत्सम्बंधित कार्गो समूह के लिए लिए गए कुल समय द्वारा विभाजित करके की जानी चाहिए। एसओआर के इस प्रकार के स्वचालित फेर बदल को हर साल किया जाएगा व समायोजित एसओआर उचित वर्ष के 1 अप्रैल, से अगले वर्ष के 31 मार्च तक जारी किया जाएगा।”

8. प्रदर्शन मानक के साथ-साथ संदर्भ प्रशुल्क अनुसूची दो 100 टन हार्बर मोबाइल क्रेन लाइसेंस के आधार पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट बर्थ पर कार्गो संचालन के लिए, वीपीटी पर स्थापित करने के लिए, वीपीटी द्वारा प्रस्तावित, **संलग्नक** के रूप के रूप में संलग्न है।

9. परिणाम में और ऊपर दिए गए कारणों से, और सामूहिक दिमाग के प्रयोग पर आधारित, यह प्राधिकरण कार्गो आपरेशनों के लिए, वीपीटी पर, लाइसेंस के आधार पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट बर्थ पर दो 100 टन हार्बर मोबाइल क्रेन स्थापित करने के लिए, संदर्भ प्रशुल्क शेड्यूल और प्रदर्शन मानकों को मंजूरी देती है।

10. प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 2.9. में, 3 साल के लिए बंदरगाह के प्रशुल्क नीति 2015 के खंड 2.9 में, 3 साल के लिए बंदरगाह के एसओआर की वैधता का प्रावधान है, जो खण्ड 2.8 और 3.2 में वर्णित के रूप में सूचीकरण के अधीन है। ऐसा होने के नाते, अनुमोदित आदेश की वैधता, क्रियान्वयन की तिथि से 3 वर्ष के लिए निर्धारित है। प्रशुल्क की वैधता को मंजूरी दी। इस विषय के एचएमसी के लिए प्रशुल्क, भारत के राजपत्र की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के बाद प्रभाव में आ जाएगा और 3 साल की अवधि के लिए प्रभाव में रहेगा तथा 3 साल बाद, दी गयी मंजूरी स्वचालित रूप से, जब तक कि विशेष रूप से इस प्राधिकरण द्वारा विस्तारित व्यपगत न हो समाप्त हो जाएगी।

11. इस प्राधिकरण द्वारा, एचएमसी के लिए, अनुमोदित प्रशुल्क अधिकतम स्तर पर है। वीपीटी को सलाह दी जाती है कि, उपयुक्त अधिकृत व्यवस्था में आवश्यक शर्त द्वारा यह सुनिश्चित करे कि अधिकृत सेवा प्रदाता संबंधित कार्गो समूह के लिए निर्धारित सीमा-शुल्क से अधिक शुल्क नहीं वसूल सके।

[फा. सं. विज्ञापन—III/4/असा./143/2015(90)]

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

## विशाखापट्टनम पत्तन न्यास

## दरों का पैमाना

निजी ऑपरेटरों द्वारा स्थापित 100 टन हार्बर मोबाइल क्रेन के उपयोग के लिए प्रभार:

(i) ड्राई बल्क कार्गो के लिए

दैनिक औसत क्रेन प्रदर्शन (मेट्रिक टन में)	अधिकतम दर प्रति टन (रुपए में)	
	विदेशी	तटवर्ती
12500	55.18	33.11
12501-13500	57.94	34.77
13501-14500	60.70	36.42

नोट: ऊपर दिखाए गए रूप में वृद्धिशील अधिकतम दरों की गणना करने के लिए, आधार दर पहली हजार टन के लिए **105%** और दूसरे हजार टन के लिए **110%**, आधार दर बढ़ाया गया था। इसी पद्धति को ही **14500** टन से परे की दर की गणना करने के लिए अपनाया जाना चाहिए।

(ii) ब्रेक बल्क कार्गो के लिए

दैनिक औसत क्रेन प्रदर्शन (मेट्रिक टन में)	अधिकतम दर प्रति टन (रुपए में)	
	विदेशी	तटवर्ती
6000	114.97	68.98
6001-7000	120.72	72.43

नोट: ऊपर दिखाए गए रूप में वृद्धिशील अधिकतम दरों की गणना करने के लिए, आधार दर पहली हजार टन के लिए **105%**, बढ़ायी गयी थी। इसी पद्धति को ही 7000 टन से परे की दर की गणना करने के लिए अपनाया जाना चाहिए।

(iii) अन्य कार्गो के लिए

दैनिक औसत क्रेन प्रदर्शन (मेट्रिक टन में)	अधिकतम दर प्रति टन (रुपए में)	
	विदेशी	तटवर्ती
3750	183.95	110.37
3751-4750	193.14	115.89

नोट: ऊपर दिखाए गए रूप में वृद्धिशील अधिकतम दरों की गणना करने के लिए, आधार दर पहली हजार टन के लिए **105%**, बढ़ायी गयी थी। इसी पद्धति को ही 4750 टन से परे की दर की गणना करने के लिए अपनाया जाना चाहिए।

नोटस:



- (i) औसत बर्थ-दिन उत्पादन की गणना के लिए सूत्र निम्नानुसार है:-

एचएमसी द्वारा कुल मात्रा लोड/अनलोड X 24 घंटे.

कुल लिया गया समय पोत प्रारंभ से पूरा होने तक

- (ii) पोत के लिए औसत बर्थ-दिन उत्पादन के अनुसार प्रारंभ से लदान/कार्गो के निर्वसन के पूरा करने तक, क्रेन किराया चार्ज की उचित दर, पूर्ण मात्रा, लोड/निर्वसन कार्गो के लिए, पोर्ट उपयोगकर्ताओं से वसूली के लिए चुना जाएगा।
- (iii) यदि एक एचएमसी एक और एचएमसी या ईएलएल क्रेन/क्रेनो के साथ काम करता है, क्रेन के लिए बर्थ-दिन उत्पादन मात्रा एचएमसी लोड मीटर द्वारा रिकॉर्ड किया गये के आधार पर तय किया जाएगा।
- (iv) एक घंटे से अधिक के लिए क्रेन की खराब स्थिति में जब तक पोत बर्थ छोड़ता है, एचएमसी द्वारा कार्गो प्रहस्तित मात्रा लोड/निर्वहन क्रेन ब्रेक-डाउन करने से पहले, क्रेन के काम के घंटे के द्वारा विभाजित और 24 द्वारा गुणा करके निर्धारित किया जाएगा।
- (v) एचएमसी के ऑपरेशन में दो घंटे से अधिक लगातार ठहराव, जो एचएमसी के कारण न हो, क्रेन, क्रेन आपरेशन में पोत के कुल समय की गणना करते समय उपयुक्त भत्ते की अनुमति होगी। उपरोक्त उद्देश्य के लिए एचएमसी के 2 घंटे से कम के ठहराव को ध्यान में नहीं लिया जाएगा। ठहराव, जो एचएमसी के कारण हो कोई भत्ते की अनुमति नहीं होगी। एचएमसी के, लोड/उतराई संचालन के काम के दौरान में सभी ठहराव दैनिक पोत प्रदर्शन रिपोर्ट में जहाज के स्टीवडॉर द्वारा प्रमाणित किए जाने आवश्यक हैं।
- (vi) क्रेन की खराब स्थिति या काम न करने के कारण पोत स्थानांतरण आवश्यक हो जाता है, तब, बर्थ से पोत के स्थानांतरण का शुल्क के अलावा, रु. 100000 (एक लाख रुपए) केवल का जुर्माना क्रेन ऑपरेटर से बरामद किया जाएगा। स्थानांतरण शुल्क तो पोत एजेंट को वापस किया जाएगा जबकि जुर्माना पोर्ट द्वारा रखा जाएगा।
- (vii) औसत उत्पादन पर विवाद की स्थिति में, पोर्ट ट्रस्ट का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- (viii) इस आदेश के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि से एक वर्ष के समापन के बाद, औसत दैनिक दर क्रेन प्रदर्शन पर शुष्क थोक कार्गो के लिए 12500 मीट्रिक टन, ब्रेक बल्क कार्गो के लिए 6000 मीट्रिक टन और अन्य माल के लिए 3750 टन का मानक स्तर के लिए करेगा, जो मुद्रास्फीति की लागत को सालाना अनुक्रमणित कर पूरा किया जाएगा और 100% भिन्नता की सीमा तक के लिए, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई), भारत सरकार द्वारा घोषित 1 जनवरी 2015 और प्रासंगिक वर्ष की 1 जनवरी, के बीच होने वाली, टैरिफ नीति की खण्ड 2.8 के अनुसार, बेंचमार्क स्तर औसत दैनिक क्रेन प्रदर्शन के मानक स्तर की उपलब्धि पूरा करने पर ही बेंचमार्क स्तर पर, औसत दैनिक क्रेन प्रदर्शन की गणना, कुल टन भार (कार्गो वार) लेते हुए, एक वर्ष में प्रहस्तित को संबंधित कार्गो समूह द्वारा कुल लिये समय से विभाजित करके किया जाता है। ऐसे स्वतः समायोजन एसओआर का हर साल बनाया जाएगा और समायोजित एसओआर प्रासंगिक वर्ष की 1 अप्रैल, से अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए लागू हो जाएगा।

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 25<sup>th</sup> May, 2015

**No. TAMP/21/2015-VPT.**—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for fixation of charges for use of 100 tonne Harbour Mobile Cranes to be installed at the East Quay and West Quay berths of VPT as in the Order appended hereto.

**Tariff Authority for Major Ports**

**Case No. TAMP/21/2015 - VPT**

**Visakhapatnam Port Trust**

---

**Applicant**

**QUORUM:**

- (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri. C.B. Singh, Member (Economic)

### ORDER

(Passed on this 15th day of May, 2015)

This case relates to the proposal received from Visakhapatnam Port Trust (VPT) for fixation of charges for use of 100 tonne Harbour Mobile Cranes (HMC) to be installed at the East Quay and West Quay berths of VPT.

2.1. The main points made by the VPT in its proposal dated 24 March, 2015 are summarised below:

- (i) The port proposes to install two Harbour Mobile Cranes of 100 Tonne capacity each at the East Quay and West Quay berths on license basis for cargo handling operations.
- (ii) TAMP vide its notification G.No. 7 dated 5 January, 2015 has notified charges for use of 100 tonne Harbour Mobile Crane installed by the private operators at the Paradip Port Trust (PPT). The rates notified in case of PPT as Reference Tariff may be considered and notified.
- (iii) However, cost calculation for 100 T HMC are carried out and are furnished alongwith draft Scale of Rates.

2.2. The calculation furnished by the VPT to arrive at the per tonne handling rate for the 100 tonne Harbour Mobile Crane is as under:

Sl. No.	Description	₹ in lakhs		
		Dry Bulk	Break Bulk	Other
<b>I</b>	<b>Optimal Capacity</b>			
(i)	Cargo Share	100%	100%	100%
(ii)	Cargo handling rate in tonnes per day	12500	6000	3750
(iii)	Cargo handling rate in tonnes per hour	744	357	223
(iv)	Total working hours in a year	4000	4000	4000
(v)	No. of HMCs considered	2	2	2
(vi)	Individual cargo capacity (i*iii*iv*v)	5,952,381	2,857,143	1,785,714
(vii)	Annual handling capacity (in lakh tonnes)	59.52	28.57	17.86
(viii)	Annual handling capacity (in million tonnes)	5.95	2.86	1.79
<b>II</b>	<b>Capital cost</b>			
(i)	Cost of 100 T capacity Harbour Mobile Crane (€ 2,890,000*68.74)	1986.59		
(ii)	Cost of two grabs (€ 320,000 * ₹68.74)	219.97		
(iii)	Cost of additional two grabs (€ 320,000 * ₹68.74)	219.97		
(iv)	Sea freight cost (€ 330,000 * ₹68.74)	226.84		
(v)	Cost for one crane	2653.36		
(vi)	Total cost for two cranes	5306.73		
(vii)	Custom Duty @ 25% of cost of HMCs	1326.68		
(viii)	Miscellaneous capital cost – 5% of capital cost	265.34		
<b>(ix)</b>	<b>Total capital cost (vi to viii)</b>	<b>6898.75</b>		
<b>III</b>	<b>Operating cost per annum</b>			
(i)	Fuel cost (Diesel – 4000 hrs. @ 70 litres per hour, ₹55.95)	313.32		

Sl. No.	Description	₹ in lakhs		
		Dry Bulk	Break Bulk	Other
	per liter*2)			
(ii)	Maintenance and repair @ 5% on equipment cost		344.94	
(iii)	Insurance @ 1% on capital cost		68.99	
(iv)	Depreciation – 10% of capital cost		689.87	
(v)	License fee (₹249.37 per sq. mtr. for 500 sq. mtrs. per annum at WQ)		1.25	
(vi)	License fee (₹213.74 per sq. mtr. for 500 sq. mtrs. per annum at EQ)		1.07	
(vii)	Other expenses @ 5% of capital cost		344.94	
	<b>Total operating cost (i to vi)</b>		<b>1764.37</b>	
IV	<b>Return on Capital Employed @ 16%</b>		<b>1103.80</b>	
V	<b>Estimated Annual Revenue Requirement</b>			
(i)	Total operating cost		1764.37	
(ii)	Return on Capital Employed		1103.80	
(iii)	<b>Total revenue requirement</b>		<b>2868.17</b>	
VI	<b>Cost per tonne</b>	<b>Dry Bulk</b>	<b>Break Bulk</b>	<b>Other</b>
(i)	Total annual revenue requirement (₹ in lakhs)	2868.17	2868.17	2868.17
(ii)	Capacity (Lakh tonnes)	59.52	28.57	17.86
(iii)	Ratio of foreign cargo to coastal cargo – last 5 years			
	Foreign	68.35%	95.65%	--
	Coastal	31.65%	4.55%	--
(iv)	<b>Cost per tonne in ₹</b>			
	<b>(a) Foreign</b>	<b>55.17</b>	<b>102.04</b>	<b>160.62</b>
	<b>(b) Coastal</b>	<b>33.10</b>	<b>61.22</b>	<b>96.37</b>

3. The proposal of the VPT seeks approval for hire charge for 100T HMC to be installed on license basis. In this context, it is relevant to draw reference to Clauses 9.1 and 9.2. of the Tariff Policy for Major Port Trusts, 2015 which governs regulation of charges levied by authorised service providers by the port. Clause 9.1. stipulates that in cases where authorisation arrangement u/s 42(3) is other than by way of a BOT concession agreement, ceiling rates will be prescribed for such services based on the proposal to be filed by the concerned Major Port Trust. Clause 9.2. of the said guidelines stipulates that in case there is no ceiling tariff prescribed in the concerned Major Port for a particular service/facility under such arrangement, the port shall adopt the tariff prescribed for the similar service/facility prescribed in any other Major Port Trust. If there is no tariff prescribed in any Major Port Trust or the rate prescribed is not representative for the cargo/service/facility envisaged, the Port Trust may file a proposal with reference to optimal capacity following the principles of 2008 guidelines or based on rated capacity [With reference to the technical specification of the service/facility/equipment]. The proposal of Port Trust shall contain the Performance Standards to be achieved by the service provider and tariff linked to Performance Standards should be proposed.

4.1. On perusing the proposal dated 24 March, 2015 filed by the VPT and in light of the provisions in Tariff Policy 2015, information gaps observed were communicated to VPT vide our letter dated 7 April, 2015. The VPT vide its letter dated 16 April, 2015 has furnished its reply on the information gaps observed by us on the subject proposal. A summary of the gaps observed by us and reply furnished by VPT thereon is tabulated below:

Sl.	Gaps observed by us	Reply furnished by VPT
-----	---------------------	------------------------

No.														
(i)	<p>The VPT on one hand has requested to notify the tariff approved by the Authority for 100T HMC (Tariff Order No.TAMP/30/2014-PPT dated 28 November, 2014, notified vide G.No.,7 dated 5 January, 2015) at the Paradip Port Trust for use of 100 tonne Harbour Mobile Crane. On the other hand, the VPT has furnished its own computation for 100T HMC for different cargo groups and has proposed rates in the SOR as per the cost computation done by the port. It is seen that the rates proposed by the port based on its computation are different from the rates notified by the Authority in the PPT case which the port has requested to notify. For example, the rate proposed by the VPT for using 100T HMC for handling foreign break bulk and other cargo are ₹102.04 per tonne and ₹160.62 per tonne respectively. Whereas, hire charge notified for 100T HMC at PPT in the Order dated 28 November, 2014 is ₹114.97 per tonne and ₹183.95 per tonne for the corresponding cargo.</p> <p>If the VPT proposes to notify the rate determined for 100T HMC at PPT, then the computation of hire charge for 100T HMC and proposing that rate in the draft SOR is also not in line with its proposal requesting the Authority to notify the rate notified in the PPT case. The VPT, therefore, to file an explicit proposal following the relevant clause of the Tariff Policy, 2015.</p>	<p>VPT hereby requests to notify the tariff approved by the Authority for 100 Tons HMC (Tariff Order No.TAMP/30/2014-PPT dated 28 November, 2014, notified vide G.No.7 dated 5 January 2015) at Paradip Port Trust (PPT) for use of 100 Tons Harbour Mobile Crane, as the modalities for deployment are the same.</p> <p>The proposal sent by VPT vide letter dated 24 March, 2015 with rates proposed by the port based on its computation is hereby withdrawn.</p> <p>Accordingly, VPT is filing an explicit proposal following the relevant Clause of Tariff Policy 2015. There is no ceiling tariff prescribed at VPT for installation of 100 Tonne HMC on license basis. Therefore, VPT proposes to adopt the ceiling tariff notified for similar facility at the PPT following clause 9.2 of Tariff Policy, 2015.</p>												
(ii)	<p>The Authority had earlier vide Order No.TAMP/16/2012-VPT dated 16 June, 2010 approved hire charge for 100 tonne HMC at the VPT to be given by the port to the authorised service provider. Subsequently, vide Order dated 28 September, 2012, the tariff approved in the June, 2010 Order was modified in view of the request made by the VPT. Since the hire charge for 100T HMC is already approved for its own port, the VPT to justify as to how its current proposal to adopt the rate for 100T HMC notified at the PPT fits into the clause 9.2. of the Tariff Policy, 2015.</p>	<p>The present proposal dated 24 March, 2015 and the TAMP Order No.TAMP/16/2012-VPT dated 16 June 2010 are different in the following aspects:</p> <table border="1" data-bbox="927 1077 1390 1440"> <thead> <tr> <th>Sl. No.</th><th>TAMP Order dated 16.06.2010</th><th>Proposal dated 24.03.2015</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Hire basis</td><td>Revenue sharing</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>MGT of 1 MMT</td><td>No MGT</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>No performance standards</td><td>Performance standards incorporated as per the PPT.</td></tr> </tbody> </table>	Sl. No.	TAMP Order dated 16.06.2010	Proposal dated 24.03.2015	1.	Hire basis	Revenue sharing	2.	MGT of 1 MMT	No MGT	3.	No performance standards	Performance standards incorporated as per the PPT.
Sl. No.	TAMP Order dated 16.06.2010	Proposal dated 24.03.2015												
1.	Hire basis	Revenue sharing												
2.	MGT of 1 MMT	No MGT												
3.	No performance standards	Performance standards incorporated as per the PPT.												
(iii)	<p>The proposal of VPT does not contain the Performance Standards to be achieved by the service provider in order to get indexation in tariff as per clause 9.3. of Tariff Policy 2015.</p>	<p>VPT is proposing to follow the Tariff Order No.TAMP/30/2014-PPT dated 28 November, 2014, notified vide G.No. 7 dated 5 January, 2015 at the PPT for use of 100 Tons Harbour Mobile Crane in toto including the performance standards.</p>												
(iv)	<p>The names of the prospective licensee/prospective authorised service providers along with the contact details viz., postal address, name of the contact person, telephone nos., fax nos., e-mail id, etc. to be consulted on the subject proposal are not provided.</p>	<p>The list of prospective licensee/prospective authorised service providers are furnished.</p>												

4.2. Further, the VPT has submitted the following:

- (i) VPT proposes to install two HMC's of 100T capacity on license basis for cargo handling operations on revenue sharing model.
- (ii) As there is no ceiling tariff prescribed at VPT for such arrangement, it is proposed vide clause 9.2 of "Policy for Determination of Tariff for Major Port Trust's 2015" to adopt the ceiling tariff notified for similar facility at PPT by TAMP.

- (iii) The proposal of VPT is, therefore, to adopt the tariff notified in respect of PPT vide TAMP G.No.7 dated 5 January, 2015 for use of 100T Harbour Mobile Crane installed by the private operators.
- (iv) The draft Scale of Rates (SOR) along with the base performance levels and tariff linked to performance standards are furnished.
- (v) The base rates proposed by the VPT in its proposal are as follows:

Cargo type	Average tonnage	Rate per tonne in ₹ (Foreign)
Dry Bulk	12500	55.18
Break Bulk	6000	114.97
Other	3750	183.95

4.3. In view of the above, the VPT has requested to consider the above replies and notify the rates as per the Tariff Order No.TAMP/30/2014-PPT dated 28 November 2014, notified vide G.No.7 dated 5 January 2015 at the PPT for use of 100 tonne Harbour Mobile Crane.

5. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal of VPT dated 16 April 2015 was forwarded to the concerned users/user organisations/service providers (as suggested by the VPT) seeking their comments latest by 28 April 2015 simultaneously to this Authority and to the VPT. The comments received from the users/user organisations/service providers were forwarded to the VPT as feedback information. The VPT vide its letter dated 5 May, 2015 and letter dated 12 May, 2015 has furnished its remarks on comments of the users/user organisations/service providers.

6. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website <http://tariffauthority.gov.in>.

7. With reference to totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:

- (i) The proposal filed by Visakhapatnam Port Trust (VPT) is for fixation of charges for use of two 100 tonne Harbour Mobile Cranes to be installed at the East Quay and West Quay berths on license basis for cargo handling operations. The VPT has proposed to adopt the rates notified by this Authority vide its Order dated 5 January 2015 in case of Paradip Port Trust (PPT) as "Reference Tariff".

This Authority has passed an Order bearing No.TAMP/30/2014-PPT dated 28 November, 2014 fixing ceiling tariff for the Harbour Mobile Crane (HMC), which the VPT has proposed to adopt it as it is without any modification.

- (ii) The Ministry of Shipping issued Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015 which was notified by this Authority in the Gazette of India on 27 January, 2015 vide G.No. 30. The said Tariff Policy has come into effect from 13 January, 2015. Clause 9.1 of the Tariff Policy 2015 states that "In cases where authorisation arrangement u/s 42(3) is other than by way of a BOT concession agreement, ceiling rates will be prescribed for such services. For this purpose, proposals for these charges should be initiated by the concerned Major Port Trust after identifying such authorised services coming under the ambit of tariff regulation and forward to this Authority. The proposal shall contain the Performance Standards to be achieved by the service provider and tariff linked to Performance Standard should be proposed and Clause 9.2 of the same policy states that "In case there is no ceiling tariff prescribed in the concerned Major Port for a particular service/facility under such arrangement, the port shall adopt the tariff prescribed for the similar service/facility prescribed in any other Major Port Trust. If there is no tariff prescribed in any Major Port Trust or the rate prescribed is not representative for the cargo/service/facility envisaged, the Port Trust may file a proposal with reference to optimal capacity following the principles of 2008 guidelines or based on rated capacity [with reference to the technical specification of the service/facility/equipment]. The proposal of Port Trust shall contain the Performance Standards to be achieved by the service provider and tariff linked to Performance Standards should be proposed." The case is analysed following the provisions prescribed in clause 9.1., 9.2. and 9.3. of the said Tariff Policy, 2015 and the present proposal needs to be governed by clause 9.1 to 9.3 of the 2015 guidelines. Further, VPT has also stated that as there is no ceiling tariff prescribed at VPT for such arrangement, it is proposed vide clause 9.2 of Policy for Determination of Tariff for Major Port Trust's 2015 to adopt the ceiling tariff notified for similar facility at PPT by this Authority.
- (iii) It is relevant here to mention that this Authority had earlier vide Order No.TAMP/16/2012-VPT dated 16 June, 2010 approved hire charge for 100 tonne HMC at the VPT to be given by the port to the

authorised service provider. Subsequently, vide Order dated 28 September, 2012, the tariff approved in the June, 2010 Order was modified at the request of VPT. Since the hire charge for 100T HMC is already approved for its own port, the VPT was asked to justify as to how its current proposal to adopt the rate for 100T HMC notified at the PPT fits into clause 9.2. of the Tariff Policy, 2015. In response, the VPT has sought to justify that the proposal dated 24 March, 2015 is on revenue sharing basis as compared with Order dated 16 June, 2010 which is based on Hire basis. The Order dated 16 June, 2010 has MGT of 1 MMT with no performance standard, whereas current proposal is with no MGT requirement but it contains performance standard. The Justification given by VPT for adoption PPT rate rather adopting own rate is found to be satisfactory.

- (iv) As rightly pointed out by the TANGEDCO, the slabwise rates initially approved in the year 2010 based on the proposal of VPT was modified and flat rate was prescribed again based on the concurrence of VPT in October, 2012. Now, the VPT has proposed to adopt the slabwise rates prescribed for HMC at PPT. Though comments of the VPT were sought in this regard by forwarding a copy of TANGEDCO comments, the reason for reverting back to slabwise rates remains unexplained. Since the proposal of VPT to adopt the rates approved for PPT, which is slabwise, is in line with the Tariff Policy, 2015, the proposal is taken up for consideration.
- (v) With reference to the reported additional burden per metric tonne in handling dry bulk cargo reported by the TANGEDCO, the proposal of VPT to engage two HMCs is with the aim of achieving better performance standards and turnaround time of vessels. The VPT expects that this will result in savings in terms of vessel related charges to the users like TANGEDCO.
- (vi) As stated earlier, the VPT has proposed to adopt the tariff fixed for HMC at the PPT vide Order dated 28 November, 2014, which was notified in the Gazette of India on 5 January, 2015. The tariff policy of 2015 subsequently announced by the Government of India, which has come into force with effect from 13 January, 2015, calls for automatic indexation of tariff to inflation from 2nd year onwards subject to achievement of performance standards as per Clause 3.2. Though the VPT has filed the proposal in March, 2015, after the implementation of Tariff Policy 2015 w.e.f. 13 January, 2015, the VPT has not proposed automatic indexation of tariff to inflation subject to achievement of performance standard. It is relevant to mention here that the Order dated 13 February, 2015 passed by this Authority fixing tariff for HMC provided by the service providers at the New Mangalore Port Trust stipulates at paragraph 10 (xviii) that:

*“As per Clause 9.3. of the said Tariff Policy where authorization arrangements under section 42(3) is other than by way of a BOT concession agreement that tariff approved by the Authority for those services shall be subject to automatic indexation as prescribed in clause 2.8 of these guidelines from the second year onwards subject to achievement of Performance Standards committed by the Major port Trusts as per Clause 3.2. If the Performance Standard is not fulfilled, no indexation would be allowed during the next year.*

*The NMPT has filed the subject proposal for fixation of tariff for the MHC to be deployed by the service providers authorized by the NMPT. Further, NMPT has adopted the norms prescribed in the tariff guidelines of 2008 for the proposed tariff for the MHC deployed by the service providers authorized by the port. As brought out in the first part of the order, the NMPT in its subject proposal has proposed tariff for bench mark level of performance and performance linked tariff by way of reward of 5% increase in the base rent if the performance achieved is 1000 tonnes higher than the bench mark level. Accordingly, a suitable note for the 100 T MHC deployed by the service providers authorized by the NMPT is prescribed in the Scale of Rates of the NMPT to enable the port to effect indexation on the approved tariff from the effective date of commencement of the second year.”*

In the Order dated 21 March, 2015, passed for fixation of tariff for port-owned 63 Tonne capacity HMC at NMPT, a suitable note is prescribed in the SOR of the NMPT to enable the port to effect indexation on the approved tariff from the effective date of commencement of the 2nd year, subject to achievement of the base performance standard levels. Following the approach adopted in the similar cases of NMPT as per the relevant clauses of the Tariff Policy 2015, a suitable note, as given below, is prescribed in the SOR of the VPT:

*“After completion of one year from the effective date of implementation of this Order, the rate for the benchmark level of the average daily crane performance at 12500 Metric Tonne for Dry Bulk Cargo, 6000 Metric Tonne for Break Bulk cargo and 3750 tonnes for Other cargo, shall be indexed annually to meet the cost of inflation to the extent of 100% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) announced by the Government of India occurring between 1st January, 2015 and 1st January of the relevant year as per Clause 2.8. of the Tariff Policy,*

*2015 subject to achievement of the benchmark level of the average daily crane performance. The Benchmark level of the average daily crane performance is to be calculated taking into account the total tonnage (cargowise) handled in a year divided by the total time taken for the respective cargo group. Such automatic adjustment of SOR will be made every year and the adjusted SOR will come into force from 1st April of the relevant year to 31 March, of the following year”.*

8. The Reference Tariff Schedule along with performance standard is attached as **Annex** for two 100 tonne Harbour Mobile Cranes to be installed at the East Quay and West Quay berths on license basis for cargo handling operations at VPT as proposed by the VPT.

9. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the Reference Tariff Schedule and the Performance Standards for Two 100 tonne Harbour Mobile Cranes to be installed at the East Quay and West Quay berths on license basis for cargo handling operations at VPT.

10. Clause 2.9. of the Tariff Policy, 2015, prescribes the validity of the SOR of the Port for 3 years, subject to indexation as mentioned in Clause 2.8 and 3.2. That being so, the validity of the tariff approved is prescribed for 3 years from the date of implementation of the Order. The tariff for the subject HMCs will come into force after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India and will remain in force for a period of 3 years. The approval accorded will automatically lapse unless specifically extended by this Authority.

11. The tariff approved by this Authority for HMC is at ceiling level. The VPT is advised to ensure by suitably including a necessary condition in the authorization arrangement that the authorized service providers do not charge more than the prescribed ceiling tariff for the respective cargo group.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./143/2015(90)]

## Annex

### Visakhapatnam Port Trust

#### Scale of Rates

Charges for use of 100 Tonne Harbour Mobile Crane installed by the private operators:

(i) For Dry Bulk Cargo

Average daily crane performance (in Metric Tonne)	Ceiling rate per tonne (in ₹)	
	Foreign	Coastal
12500	55.18	33.11
12501-13500	57.94	34.77
13501-14500	60.70	36.42

**Note:** To calculate the incremental ceiling rates as shown above, the base rate was enhanced to 105% for first thousand tonnes and for the 2nd thousand tonnes the rate was enhanced to 110% of the base rate. The same methodology shall also be adopted to calculate the rate beyond 14500 tonnes.

(ii) For Break Bulk Cargo

Average daily crane performance (in Metric Tonne)	Ceiling rate per tonne (in ₹)	
	Foreign	Coastal
6000	114.97	68.98
6001-7000	120.72	72.43

**Note:** To calculate the incremental ceiling rates as shown above, the base rate was enhanced to 105% for first thousand tonnes. The same methodology shall also be adopted to calculate the rate beyond 7000 tonnes.

(iii) For Other cargo

Average daily crane performance (in Metric Tonne)	Ceiling rate per tonne (in ₹)	
	Foreign	Coastal
3750	183.95	110.37
3751-4750	193.14	115.89

**Note:** To calculate the incremental ceiling rates as shown above, the base rate was enhanced to 105% for first thousand tonnes. The same methodology shall also be adopted to calculate the rate beyond 4750 tonnes.

**Notes:**

(i) The formula for calculation of average berth-day output is as follows:—

$$\frac{\text{Total Quantity loaded/unloaded by HMC}}{\text{Total time taken from vessel commencement to completion}} \times 24 \text{ hrs.}$$

Total time taken from vessel commencement to completion

- (ii) According to the average berth-day output for the vessel from commencement to completion of loading/discharge of cargo, the appropriate rate of crane hire charge will be chosen for recovery from Port users for the full quantity of cargo loaded/discharged.
- (iii) If one HMC works with another HMC or ELL crane/s, the Berth-day output for the crane will be ascertained on the basis of the quantity as recorded by the HMC's load meter.
- (iv) In case of breakdown of the crane for more than one hour till the vessel leaves the berth, the quantity handled by HMC will be determined taking into account cargo loaded/discharged prior to break-down divided by crane working hours and multiplied by 24.
- (v) In case of stoppages of operation of HMC for more than two hours at a stretch for reasons not attributable to the HMC, appropriate allowance will be allowed to the crane while calculating the total time of crane operation in the vessel. Stoppages of HMC for less than 2 hours will not be taken into consideration for the above purpose. No allowance will be allowed for stoppages attributable to the HMC. All stoppages in loading/unloading operations during working of HMC are required to be certified by the Stevedore of the vessel in the daily vessel performance report.
- (vi) In case shifting of a vessel becomes necessary due to breakdown/non-performance of HMC, the shifting charges of the vessel from berth to anchorage will be recovered from the crane operator in addition to a penalty of ₹1,00,000/- (Rupees one lakh ) only . The shifting charges so recovered will be refunded to the vessel's agent while the penalty will be retained by the Port.
- (vii) In case of dispute on the average output, the decision of the Port Trust will be final and binding.
- (viii) After completion of one year from the effective date of implementation of this Order, the rate for the benchmark level of the average daily crane performance at 12500 Metric Tonne for Dry Bulk Cargo, 6000 Metric Tonne for Break Bulk cargo and 3750 tonnes for Other cargo, shall be indexed annually to meet the cost of inflation to the extent of 100% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) announced by the Government of India occurring between 1st January, 2015 and 1st January of the relevant year as per Clause 2.8. of the Tariff Policy, 2015 subject to achievement of the benchmark level of the average daily crane performance. The Benchmark level of the average daily crane performance is to be calculated taking into account the total tonnage (cargowise) handled in a year divided by the total time taken for the respective cargo group. Such automatic adjustment of SOR will be made every year and the adjusted SOR will come into force from 1st April, of the relevant year to 31 March, of the following year.